

प्रेषक,

एस0 राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहसदून: दिनांक 21 फरवरी, 2014

विषय:-राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना "हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सी0 3917/न0दे0क0यो0/1052(4)2013 दिनांक 12-02-2014 के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार सहायतित "नन्दा देवी कन्या योजना" के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या- 737/XVII(2)/2009 दिनांक 27-05-2009 एवं संशोधित शा0 संख्या- 3020/XVII(2)/2010 दिनांक 06-01-2011 तथा शा0 संख्या- 778/XVII(2)/2013 दिनांक 03-04-2013 में एतद्वारा निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

(1) शासनादेश संख्या 737/XVII(2)/2009 दिनांक 27-05-2009 के प्रस्तर-1 के अनुसार राज्य सरकार सहायतित योजना "नन्दा देवी कन्या योजना" को अब नये स्वरूप में "हमारी कन्या हमारा अभिमान" पढ़ा जाय।

(2) शासनादेश संख्या 737/XVII(2)/2009 दिनांक 27-05-2009 के प्रस्तर-2 के अनुसार कन्या शिशु के जन्म के समय प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को रू0 5000/- से बढ़ाकर रू0 15000/- किया जाता है। आर्थिक सहायता की बढ़ी हुई धनराशि रू0 15000/- में से रू0 5000/- की धनराशि कन्या शिशु के जन्म के समय Account Payee Check के माध्यम से कन्या के अभिभावक को एवं रू0 5000/- की धनराशि कन्या के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर Account Payee Check के माध्यम से कन्या के अभिभावक को तथा ब्याज सहित अवशेष धनराशि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कन्या को प्रदान की जायेगी।

(3) संशोधित शासनादेश संख्या- 3020/XVII(2)/2010 दिनांक 06-01-2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार बी0पी0एल0 परिवार के साथ ही ऐसे परिवार में जन्मी बालिकायें जिनके परिवार की वार्षिक आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 36000/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 42000/- हों भी योजना का लाभ पाने की पात्र होंगी।

(4) I- संशोधित शासनादेश संख्या- 778/XVII(2)/2013 दिनांक 03-04-2013 के प्रस्तर-1 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होने विषयक स्थाई निवास प्रमाण पत्र अथवा उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा परिवार

रजिस्टर की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर भी कन्या शिशु को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(4) II- उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के अनुसार योजना के प्रारम्भ होने के समय से अब तक पैदा हुई ऐसी बालिकाओं को- जो इस योजना से लाभान्वित होने से वंचित रह गई हैं- लाभान्वित करने के लिये पूर्व की 01 वर्ष की अवधि (बालिका के जन्म लेने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर आवेदन करने की पात्रता) का प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए एक बार (One Time) शिथिलता प्रदान करते हुए शासनादेश निर्गत होने की तिथि के 01 वर्ष के अन्दर ऐसी समस्त पात्र बालिकाओं को लाभान्वित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

2- यह आदेश उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायें। शासनादेश संख्या 737/XVII(2)/2009 दिनांक 27-05-2009 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 230 (P)/XXVII (1)/2013-14 दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या: 386 /XVII(4)/2014 /14/09 TC तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव